for 1990-91 and the corresponding figures for 1989-90 ;

(b) the amount allocated out of this plan, for the Kashmir Valley during the corresponding periods; and

(c) whether Government are planning to increase the per capita income in the Valley ; if so, what are the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI BHAGEY GOBARDHAN) : (a) The agreed outlay for the Annual Plan 1990-91 is Rs. 650 crores as against Rs. 550 crores for the Annual Plan 1989-90.

(b) No separate allocation is made for the Kashmir Valley in the approved outlay by the Planning Commission.

(c) The object of the successive Five Year Plans/Annual Plans has been to improve the living standard of the people through the developmental efforts. In this process the State income also increases.

The par capita income in Jammu and Kashmir State has been consistently rising from year to year. The per capita income in the State at current prices has increased from Rs. 1455 in 1980-81 to Rs. 2344 in 1986-87 as per the Central Statistical Organisation.

विश्वायतन योगाश्रम द्वारा संचालित योग डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश

2216. **श्री राम नरेश यादव :** क्या प्रधान मंत्री 8 मई, 1990 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न सं० 452 के लिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1990 में विश्वायतन योगाश्रम कटरा में डिप्लोमा तथा डिग्री पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण ले रहे व्यक्तियों की संख्या क्या थी तथा वर्तमान में प्रशिक्षण ले रहे व्यक्तियों की देशवार संख्या क्या है; तथा वहां प्रवेश लेने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या वर्तमान में विश्वायतन योगाश्रम बंद पड़ा है; यदि हां, तो यह कब से बंद पड़ा है और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह योगाश्रम सरकार से मान्यताप्राप्त है, यदि नहीं, तो क्या सरकार का ध्यान विश्वायतन योगाश्रम के उस विज्ञापन की ओर दिलाया गया है जो 18 अगस्त, 1989 के हिन्दुस्तान टाइम्स समाचारपत्र में शिक्षा तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा मान्यताप्राप्त एक वर्ष के योग प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के संबंध में प्रकाशित हुआ था ; और

(घ) यदि हां, तो उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्होंने वहां प्रवेश लिया और उनकी परीक्षाओं के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) प्राप्त की गई सूचना के अनुसार विश्वायतन योग आश्रम, कटरा में मार्च, 1990 में डिप्लोमा पाठ्यक्रम में 70 व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे और यह आश्रम तालाबन्दी के कारण 30 अप्रैल, 1990 से बंद है ।

(ग) योग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के संबंध में 18 अगस्त, 1989 के हिन्दुस्तान टाइम्स में विश्वायतन योग आश्रम का कोई विज्ञापन नहीं छपा है । तथापि, हाल ही में 13 अगस्त, 1989 के हिन्दुस्तान टाइम्स अंक में ऐसे एक विज्ञापन की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है । मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) इस श्रेणी की संस्थाओं को मान्यता नहीं देती यद्यपि इस संस्था को 1977 तक वित्तीय सहायता दी गई थी ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Environment clearance for lease of marble quarries near Ambaji in Gujarat

2217. SRRI VITHALBHAI M. PATEL : Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the proposal of Forests and Environment Department of Gujarat to permit them to lease marble quarries in Ambaji forest area in Banaskantha in that State has been pending with Government since long ;

(b) if so, whether Government are aware of the mass unemployment caused due to closure of these quarries due to non-clearance of the proposal ; and

(c) if so, by when the proposal is likely to be given clearance ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (MRS. MANEKA GANDHI): (a) & (c) A proposal for denotification of 198.28 hect. of marble mining lease area Ambaji in Banaskantha district of Gujarat State was received by the Central Government in July 1988 for according clearance under Forest (Conservation) Act, 1980. However, no proposal for clearance from Environmental angle has so far been received in this Ministry. The forest clearance and environment clearance are to be given simultaneously.

(b) Information is being collected from State Government and will be laid on the Table of the House.

देश में भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्व्यवस्थापन

2218. **श्री राम नरेश यादव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में ऐसे कितने भूतपूर्व सैनिक हैं जिन्हें अभी पुनर्व्यस्थापित किया जाना है ;

(ख) क्या सरकार उन्हें पुनर्व्यवस्थापित करने के संबंध में कोई योजना बना रही है, यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. राजा रमन्ना) : (क) विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों के संबंध में रखे गए चालू रजिस्टरों के अनुसार 1-1-1990 को 2,59,780 भूतपूर्व सैनिकों के लिए अभी रोजगार उपलब्ध कराया जाना है ।

(ख) भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए व्यापक कार्यक्रम बनाया गया है । केन्द्र सरकार ने, केन्द्रीय सरकार के विभागों और राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में समूह "ग" और समूह "घ" के पदों पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है । अधिकतर राज्य सरकारों ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए सिविल पद अलग-अलग मात्रा में आरक्षित करने की व्यवस्था की है । इसके अतिरिक्त भूतपूर्व सैनिकों को स्वःरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं । इनमें "सेमफेक्स-1" योजना शामिल है । इस योजना के अंतर्गत लघु उद्योग स्थापित करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । "सेमफेक्स-2" योजना के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों को ग्रामीण क्षेत्रों में लाभकारी कृषि और गैर-कृषि काम धन्धे शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, पेट्रोलियम उत्पाद एजेंसियां आबंटित की जाती हैं, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया की ऐजेंसियों को आबंटन किया जाता है, कोयले एवं पैट्रोलियम उत्पादों के लिए परिवहन ऐजेंसियां दी जाती हैं, भूतपूर्व सैनिकों की लघु उद्योग यूनिटों द्वारा रक्षा स्थापनाओं को सप्लाई किए गए सामान की कीमत पर आर्थिक सहायता दी जाती है, इत्यादि ।